

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

पेपर- 7: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान

भाग - II

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें

वर्किंग नोट्स को उत्तर का हिस्सा बनाना चाहिए

सभी प्रश्न कर-निर्धारण वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं, जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा गया हो।

प्रश्न 1

मैसर्स कावेरी लिमिटेड, एक निर्माण कंपनी, जिसका वार्षिक कारोबार ₹ 6,000 लाख है, ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों के डेबिट/ऋण के बाद ₹ 850 लाख का शुद्ध लाभ दिखाया:

- (a) कंपनी अधिनियम, 65 लाख के अनुसार मूल्यहास
- (b) मार्च, 2022 के महीने के लिए कर्मचारी के अंशदान की समान राशि के साथ-साथ ₹ 18 लाख के ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान 20 मई, 2022 को प्रेषित किया गया था। (कर्मचारी के ईपीएफ खाते में धन जमा करने की नियत तारीख 15 अप्रैल, 2022 है।)
- (c) भुगतान किए गए जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना के रूप में ₹ 10,500 और कर जमा करने में देरी के लिए ब्याज के लिए ₹ 15,400 की राशि शामिल है।
- (d) अधिसूचित कौशल विकास परियोजना के तहत ₹ 10 लाख की राशि खर्च की गई थी। 35CCD.
- (e) कारखाने में आग से पुरानी मशीनरी के नष्ट होने पर ₹ 20 लाख की हानि तथा इस मशीनरी पर ₹ 5 लाख कतरन मूल्य के रूप में प्राप्त हुए। बीमा कंपनी ने घोर लापरवाही के आरोप में कंपनी के दावे को स्वीकार नहीं किया।

- (f) एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश ₹ 15 लाख जिसमें कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 32% हिस्सा है, इस आय को अर्जित करने पर ₹ 50,000 भी खर्च किए गए थे।
- (g) एक घरेलू कंपनी एक्स लिमिटेड को एक इमारत की बिक्री पर ₹ 15 लाख का लाभ, जिसके पूरे शेयर निर्धारित कंपनी के पास हैं। भवन कावेरी लिमिटेड द्वारा 1 दिसंबर, 2020 को अधिग्रहण किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

- (i) आयकर नियम, 1962 के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्यहास ₹ 92 लाख है।
- (ii) पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 जनवरी, 2021 को ₹ 20 लाख का एक नया संयंत्र और मशीनरी खरीदी है। इस मशीन पर अतिरिक्त मूल्यहास का शेष पिछले वर्ष 2021-22 के लिए गणना किए गए मूल्यहास में शामिल नहीं है।

पेपर 7 के लिए सुझाए गए उत्तर: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो मई 2022 की परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष कर निर्धारण वर्ष 2022-23 है।

- (iii) कंपनी ने कारखाने के भवन की मरम्मत के लिए 31 मार्च, 2021 को एक उप-ठेकेदार के खाते में ₹ 7 लाख की राशि जमा की थी। इस तरह के भुगतान पर काटे गए कर को 31 दिसंबर, 2021 को प्रेषित किया गया था।
- (iv) 15 मई, 2022 को मैसर्स कावेरी लिमिटेड ने 20 लाख रुपये का लाभांश घोषित और वितरित किया।

सहायक वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स कावेरी लिमिटेड द्वारा देय कुल आय और कर की गणना करें, प्रत्येक मद के उपचार के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए। मान लें कि कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए खंड 115बीबीए को चुना है। (14 अंक)

उत्तर

धारा 115बीबीए के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स कावेरी लिमिटेड की
कुल आय की गणना

	विवरण (ब्यौरा)	राशि (₹ में)	
I.	<p>व्यापार और पेशे से लाभ और मुनाफा लाभ और हानि के विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ</p> <p>जोड़ें: डेबिट किए गए मद लेकिन अलग से विचार किए जाने या अस्वीकृत किए जाने के लिए</p> <p>(a) कंपनी अधिनियम के अनुसार मूल्यहास 65,00,000</p> <p>(b) ईपीएफ में कर्मचारियों का योगदान 18,00,000 [चूंकि ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान पीएफ अधिनियम के तहत देय तिथि पर या उससे पहले जमा नहीं किया गया है, यह स्पष्टीकरण 1 और 2 के साथ पठित धारा 36(1)(वीए) के अनुसार कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। चूंकि, इसे लाभ और हानि के विवरण में डेबिट कर दिया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना के लिए वापस जोड़ना होगा।]</p> <p>(c) ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान शून्य [धारा 43B के अनुसार, ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान कटौती के रूप में स्वीकार्य है क्योंकि इसे धारा 139(1) के तहत प्रतिलाभ दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया गया है। चूंकि, इसे लाभ और हानि के विवरण</p>		8,50,00,000

	में नामे कर दिया गया है, कोई और समायोजन आवश्यक नहीं है]	
(d)	जीएसटी रिटर्न देर से फाइल करने पर जुर्माना [जीएसटी प्रतिलाभ दाखिल करने में देरी के लिए लगाया गया जुर्माना कटौती योग्य नहीं है क्योंकि यह कानून के उल्लंघन के कारण निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिलाभ दाखिल करने की आवश्यकता है। ¹ . चूँकि, इसे लाभ और हानि के विवरण में डेबिट कर दिया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना के लिए वापस जोड़ना होगा]	10,500
(e)	जीएसटी जमा करने में देरी के लिए ब्याज [जीएसटी जमा करने में देरी के लिए भुगतान किया गया ब्याज क्षतिपूर्ति प्रकृति का है और इसलिए, कटौती के रूप में स्वीकार्य है। चूँकि, इसे लाभ और हानि के विवरण में नामे कर दिया गया है, कोई और समायोजन आवश्यक नहीं है]	शून्य
(f)	धारा 35सीसीडी के तहत अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय [धारा 35सीसीडी के तहत अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने धारा 115बीबीए का विकल्प चुना है]	10,00,000
(g)	मशीनरी के आग द्वारा नष्ट होने से हानि	

¹ सीआईटी बनाम रतनचंद भोलानाथ (एस.एस) (1986) 160 आईटीआर 500 (मध्यप्रदेश)

<p>[मशीनरी के आग द्वारा नष्ट होने से हुई ₹20 लाख की हानि कटौती योग्य नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में पूँजी है। चूँकि, हानि को लाभ और हानि के विवरण में डेबिट कर दिया गया है, इसलिए, इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय वापस जोड़ा जाना आवश्यक है]</p>	20,00,000	
<p>(h) लाभांश आय अर्जित करने पर व्यय [लाभांश आय अर्जित करने पर व्यय की स्वीकार्यता या अन्यथा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत विचार किया जाना है। चूँकि, व्यय को लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा]</p>	50,000	
<p>घटाएँ: मदें ऋण की गईं लेकिन किसी अन्य मद/व्यय के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय हैं लेकिन डेबिट नहीं की गई हैं</p>		
<p>1. मशीनरी का स्ट्रैप मूल्य [मशीनरी का स्ट्रैप मूल्य, प्रकृति में पूँजी होने के कारण, मशीनरी के डब्लूडीवी से कम किया जाना चाहिए। चूँकि, इसे लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है, इसलिए, इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना चाहिए]</p>	5,00,000	
<p>2. विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश [विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत कर योग्य है।</p>	15,00,000	
		<p><u>1,13,60,500</u> 9,63,60,500</p>

	चूँकि, उक्त लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना चाहिए]	
3.	100% अनुषंगी को भूमि के प्लॉट की बिक्री पर लाभ [करदेयता या अन्यथा "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के तहत विचार किया जाना है। चूँकि, मुआवजे को लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना चाहिए]	15,00,000
4.	आयकर नियमों के अनुसार मूल्यहास सामान्य मूल्यहास अतिरिक्त मूल्यहास [यद्यपि पिछले वर्ष की शेष 10% अतिरिक्त मूल्यहास चालू वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार्य है, क्योंकि कंपनी धारा 115बीए का विकल्प चुन रही है, इस मामले में अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति नहीं है]	92,00,000 शून्य
5.	उप-ठेकेदार को भुगतान जहाँ पिछले साल कटौती किए गए कर प्रतिलाभ (रिटर्न) दाखिल करने की नियत तारीख के बाद भेजा गया था [₹7 लाख का 30%, उप-ठेकेदार को भुगतान होने के कारण, निर्धारण वर्ष 2021-22 की व्यावसायिक आय की गणना करते समय धारा 40 (a) (ia) के तहत	2,10,000

	अस्वीकृत हो जाता है, चूँकि, कर कटौती प्रतिलाभ (रिटर्न) दाखिल करने की नियत तारीख के बाद प्रेषित की गई थी। हालाँकि, यह निर्धारण वर्ष 2022-23 में स्वीकार्य है, क्योंकि 31.12.2021 को प्रेषण किया गया है]		1,29,10,000
			8,34,50,500
II	पूँजीगत लाभ		
	1. 100% भारतीय अनुषंगी को भवन की बिक्री पर लाभ [24 महीने से कम समय के लिए रखे गए भवन की बिक्री पर अल्पकालिक पूँजीगत लाभ उत्पन्न होता है। हालाँकि, इस मामले में, चूँकि, स्थानांतरण 100% सहायक कंपनी को है और सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है, यह धारा 47 (iv) के अनुसार पूँजीगत लाभ कर लगाने के लिए स्थानांतरण नहीं होगा।		शून्य
III	अन्य स्रोतों से आय		
	निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से लाभांश आय [चूँकि मैसर्स कावेरी लिमिटेड के पास विदेशी कंपनी में 26% या अधिक इक्विटी शेयर हैं, ऐसी विदेशी कंपनी धारा 115बीबीडी के तहत एक निर्दिष्ट विदेशी कंपनी है। निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से लाभांश आय अर्जित करने पर व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।]		15,00,000
	सम्पूर्ण कुल आय घटाएँ: अध्याय VI-A के तहत कटौती		8,49,50,500

अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में धारा 80एम के तहत कटौती [निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश के रूप में ₹ 15 लाख से कम होने के नाते, और ₹ 20 लाख, मैसर्स कावेरी लिमिटेड द्वारा निर्दिष्ट देय तिथि पर या उससे पहले वितरित लाभांश के रूप में /आय की विवरणी दाखिल करने की धारा 139(1)]	15,00,000
कुल आय	8,34,50,500

धारा 115बीबीए के तहत निर्धारण A.Y. 2022 2022-23 के लिए मैसर्स कावेरी लिमिटेड द्वारा देय कर की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹
व्यावसायिक आय पर कर @ 8,34,50,500 के 22% की दर से	1,83,59,110
जोड़ें: अधिभार @ 10%	<u>18,35,911</u>
	2,01,95,021
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%	<u>8,07,801</u>
कर देयता	<u>2,10,02,822</u>
देय कर (पूर्णांक में)	2,10,02,820

प्रश्न 2

(a) बिल्डवेल लिमिटेड, एक रियल एस्टेट इन्वैस्टिमेंट ट्रस्ट है, जो प्रासंगिक सेबी विनियमों के तहत पंजीकृत है, एचएटीएस लिमिटेड में 51% शेयर रखता है बिल्डवेल लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी आय के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है।

- एचएटीएस लिमिटेड से ब्याज आय - ₹ 10 करोड़
- एचएटीएस लिमिटेड से ब्याज आय - ₹ 10 करोड़
- विकासात्मक संपत्तियों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ - ₹ 1 करोड़
- कंपनियों के असूचीबद्ध ऋणपत्र में निवेश से प्राप्त ब्याज - ₹ 10 लाख
- सीधे स्वामित्व वाली अचल संपत्ति संपत्ति से किराये की आय - ₹ 2.5 करोड़

श्री विजय, एक निवासी भारतीय, आरईआईटी की 70% इकाइयाँ रखते हैं। वर्ष के दौरान उनकी कोई अन्य आय नहीं है।

मैसर्स बिल्डवेल लिमिटेड और श्री विजय के हाथों देय कुल आय और कर की गणना करें।

ध्यान दें : हैट्स लिमिटेड ने धारा 115बीबीए के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है और श्री विजय ने धारा 115बीसीए का विकल्प चुना है। टीडीएस निहितार्थों पर ध्यान न दें। **(8 अंक)**

- (b) सुश्री ब्लैक एंड ब्राउन एसए, (बीएनबी), कंट्री एक्स में निगमित एक कंपनी नियुक्त की गई श्री लाल सिंह भारत में एक दलाल के रूप में। लाल सिंह आदतन भारत में माल या माल का स्टॉक रखता है और बीएनबी सहित विभिन्न अनिवासी संस्थाओं की ओर से नियमित रूप से इसकी वितरण करता है। बीएनबी का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान या पेशे का कोई निश्चित स्थान नहीं है। साथ ही, भारत और देश एक्स के बीच कोई डीटीए नहीं है।

बीएनबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से निम्नलिखित आय अर्जित की:

श्री लाल सिंह द्वारा माल की वितरण से आय ₹ 2 करोड़ है।

तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क ₹ 55 लाख (ऐसी आय अर्जित करने पर खर्च किए गए ₹ 6 लाख घटाने के बाद)

व्हाइट लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी (अमेरिकी डॉलर में अभिदत्त) के गैर-सूचीबद्ध ऋणपत्र की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ₹ 14 लाख

बीएनबी ने भारत से अर्जित उपर्युक्त आय के संबंध में देश एक्स में कर के रूप में ₹50 लाख के बराबर राशि का भुगतान किया था।

आपको भारत में बीएनबी द्वारा अर्जित आय की करदेयता के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करने और उपरोक्त आय पर बीएनबी द्वारा देय कर की गणना करने की आवश्यकता है। **(6 अंक)**

उत्तर

(a) मैसर्स बिल्डवेल लिमिटेड (आरईआईटी) और श्री विजय (इकाई-धारक) के हाथों देय कुल आय और कर की गणना

विवरण (ब्यौरा)	बिल्डवेल (आरईआई टी)	श्री विजय यूनिट धारक
<p>(i) एचएटीएस लिमिटेड (एसपीवी) से ₹ 10 करोड़ की ब्याज आय</p> <p>एसपीवी से ब्याज आय धारा 10(23एफसी)(ए) के आधार पर आरईआईटी के हाथों छूट प्राप्त होगी।</p> <p>इकाई धारकों को वितरित ऐसी ब्याज आय के घटक को धारा 115यूए(3) के अनुसार इकाई धारकों की आय माना जाएगा। तदनुसार, ₹ 7 करोड़, ₹ 10 करोड़ का 70% होने के नाते, इकाईधारक श्री विजय के हाथों कर योग्य होगा।</p>	शून्य	7,00,00,000
<p>(ii) एचएटीएस लिमिटेड (एसपीवी) से ₹ 3 करोड़ की लाभांश आय</p> <p>एसपीवी द्वारा आरईआईटी को वितरित लाभांश धारा 10(23एफसी)(बी) के आधार पर आरईआईटी के हाथों छूट प्राप्त है।</p> <p>इकाईधारकों को वितरित ऐसी लाभांश आय का घटक धारा 10(23एफडी) में निहित अपवाद के आधार पर इकाईधारकों के हाथों कर योग्य है, क्योंकि एचएटीएस लिमिटेड (एसपीवी) ने धारा 115बीएए के तहत विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, ₹ 2.10 करोड़, ₹ 3 करोड़ का 70%</p>	शून्य	2,10,00,000

होने के नाते, इकाईधारक श्री विजय के हाथों कर योग्य होगा।		
<p>(iii) विकासात्मक संपत्तियों की बिक्री पर ₹1 करोड़ का अल्पकालिक पूंजीगत लाभ:</p> <p>धारा 115यूए(2) के अनुसार विकास संपत्तियों की बिक्री पर एसटीसीजी आरईआईटी के हाथों 42.744% की अधिकतम सीमांत दर पर कर योग्य है।</p> <p>धारा 10(23एफडी) में निहित छूट के आधार पर, उन्हें वितरित आय के पूंजीगत लाभ घटक पर यूनिट धारकों के पास कोई कर देयता नहीं होगी।</p>	1,00,00,000	शून्य
<p>(iv) कंपनियों के असूचीबद्ध ऋणपत्र में निवेश के संबंध में प्राप्त ₹ 10 लाख का ब्याज</p> <p>ऐसा ब्याज 42.744% की दर से कर योग्य है, जो कि धारा 115यूए(2) के अनुसार आरईआईटी के हाथों अधिकतम सीमांत दर है।</p> <p>धारा 10(23FD) के आधार पर यूनिट धारकों को उन्हें वितरित आय के ब्याज घटक पर कोई कर देयता नहीं होगी।</p>	10,00,000	शून्य
<p>(v) सीधे स्वामित्व वाली अचल संपत्ति परिसंपत्ति से ₹2.50 करोड़ की किराये की आय:</p> <p>धारा 10(23एफसीए) के अनुसार आरईआईटी के सीधे स्वामित्व वाली किसी भी अचल संपत्ति संपत्ति को किराए पर लेने या पट्टे पर देने या किराए पर देने के माध्यम से होने वाली आय को आरईआईटी के हाथों छूट प्राप्त है।</p>	शून्य	1,75,00,000

हालांकि, धारा 115यूए(3) के अनुसार इकाईधारकों को वितरित ऐसी किराये की आय के घटक को इकाई धारकों की आय माना जाता है। तदनुसार, ₹ 1.75 करोड़, ₹ 2.5 करोड़ का 70% होने के नाते श्री विजय के हाथों कर योग्य होगा।		
कुल आय	1,10,00,000	10,85,00,000

विवरण (ब्यौरा)	₹	₹
देय कर की गणना आरईआईटी (मैसर्स बिल्डवेल) के हाथों में ₹ 1,10,00,000 की कुल आय पर कर @ 42.744% [अधिकतम सीमांत दर - 30% + अधिभार @ 37% + उपकर @ 4%] इकाईधारक के हाथों में, श्री विजय जिन्होंने धारा 115बीसीए का विकल्प चुना है ₹2,50,000 तक ₹2,50,001- ₹5,00,000 @5% ₹5,00,001- ₹7,50,000 @10% ₹7,50,001- ₹10,00,000 @15% ₹10,00,001 - ₹12,50,000 @20% ₹12,50,001 - ₹15,00,000 @25% ₹15,00,001- ₹10,85,00,000 @30% जोड़ें: 37% सरचार्ज (चूंकि उसकी कुल आय ₹ 5 करोड़ से अधिक है)	47,01,840	शून्य 12,500 25,000 37,500 50,000 62,500 <u>3,21,00,000</u> 3,22,87,500 <u>1,19,46,375</u> 4,42,33,875

जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%		17,69,355
वसूल किया गया		<u>4,60,03,230</u>

टिप्पणियाँ (नोट्स):

- (i) यह माना गया है कि आरईआईटी द्वारा प्राप्त आय का 100% उसके इकाईधारकों को वितरित किया जाता है।
- (ii) चूंकि प्रश्न में विशेष रूप से अंत में टीडीएस निहितार्थों को नजरअंदाज करने के लिए एक नोट शामिल है, इसलिए देय कर की गणना स्रोत पर काटे गए कर की राशि को घटाए बिना की जाती है।

(b) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए बीएनबी की कर देनदारी की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹
बीएनबी के एक दलाल श्री लाल सिंह द्वारा माल की वितरण से आय धारा 9(1)(i) के अनुसार, एक विदेशी कंपनी, व्यावसायिक लाभ को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा, यदि ऐसी आय भारत में किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से या उससे उत्पन्न होती है। बीएनबी के मामले में, व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि श्री लाल सिंह उसकी ओर से कार्य करते हुए आदतन भारत में माल या माल का एक स्टॉक रखता है जिससे वह नियमित रूप से उसकी ओर से माल या माल वितरित करता है। इसलिए, ऐसी आय बीएनबी के हाथों कर योग्य है।	2,00,00,0
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (एफटीएस) एफटीएस एक विदेशी कंपनी के हाथों कर योग्य होगा, क्योंकि एफटीएस भारत में प्राप्त किया गया है। इसलिए, इस तरह की आय अर्जित करने पर व्यय में कटौती के बाद ऐसे एफटीएस बीएनबी के हाथों में कर योग्य होंगे। तदनुसार, ₹ 55 लाख कर योग्य होगा।	55,00,000
व्हाइट लिमिटेड की एक भारतीय कंपनी के गैर-सूचीबद्ध ऋणपत्र	

की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, बीएनबी के हाथों कर योग्य होगा, क्योंकि यह भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति से उत्पन्न होता है।

कुल आय

2,69,00,0

कुल आय पर कर

धारा 112(1)(c)(iii) के अनुसार दीर्घकालीन
पूंजीगत लाभ @ 10% पर कर

1,40,000

अन्य आय @ 2,55,00,000 पर 40% की दर से कर

	1,03,40,0
जोड़ें: अधिशुल्क@ 2% कुल आय के बाद से > ₹ 1 करोड़ लेकिन ≤ ₹10 करोड़	<u>2,06,800</u>
	1,05,46,8
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% कर देयता	<u>4,21,872</u> <u>1,09,68,6</u>
कर देयता (पूर्णांक में)	1,09,68,6
<p>ध्यान दें - देश एक्स में कर के रूप में भुगतान किए गए ₹50 लाख के संबंध में कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि देश एक्स के साथ कोई डीटीए नहीं है और धारा 91 के प्रावधान ऐसे मामलों में कटौती के लिए प्रदान करते हैं जहां कोई डीटीए बीएनबी पर लागू नहीं होगा, एक विदेशी कंपनी।</p>	

वैकल्पिक उत्तर

यदि यह माना जाता है कि एफ़टीएस के लिए समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो एफ़टीएस धारा 115ए के तहत 10% की दर से कर योग्य होगा। कर देनदारी इस प्रकार होगी -

विवरण (ब्यौरा)	₹
बीएनबी के एक दलाल श्री लाल सिंह द्वारा माल की वितरण से आय	2,00,00,0
धारा 9(1)(i) के अनुसार, एक विदेशी कंपनी, यूरेनस कॉर्पोरेशन के व्यावसायिक लाभ को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना	

जाएगा, यदि ऐसी आय भारत में किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से या उससे उत्पन्न होती है। बीएनबी के मामले में, व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि श्री लाल सिंह उसकी ओर से कार्य करते हुए आदतन भारत में माल या माल का एक स्टॉक रखता है जिससे वह नियमित रूप से उसकी ओर से माल या माल वितरित करता है। इसलिए, ऐसी आय बीएनबी के हाथों कर योग्य है।	
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (एफटीएस) एफटीएस एक विदेशी कंपनी के हाथों कर योग्य होगा, क्योंकि एफटीएस भारत में प्राप्त किया गया है। यह मानते हुए कि समझौते को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, धारा 115ए के अनुसार, इस तरह की आय अर्जित करने पर व्यय में कटौती किए बिना ऐसे एफटीएस बीएनबी के हाथों कर योग्य होंगे। तदनुसार, ₹ 61 लाख कर योग्य होगा।	61,00,00
व्हाइट लिमिटेड की एक भारतीय कंपनी के गैर-सूचीबद्ध ऋणपत्र की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ , बीएनबी के हाथों कर योग्य होगा, क्योंकि यह भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति से उत्पन्न होता है।	14,00,00
कुल आय	2,75,00,000

कर देयता की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹
2,75,00,000 की कुल आय पर कर	
धारा 112(1)(c)(iii) के अनुसार दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ @ 10% पर कर	1,40,000
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर कर @ 61,00,000 पर 10%	6,10,000
अन्य आय पर ₹ 2,00,00,000 @ 40% कर	

क@ 2% कुल आय के बाद से > ₹ 1 करोड़ लेकिन ≤ ₹10 करोड़	87,50,00
और शिक्षा उपकर @ 4%	89,25,00

कर देयता	<u>92,82.00</u>
----------	-----------------

प्रश्न 3

(a) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धर्मार्थ न्यास/संस्थाओं के निम्नलिखित स्वतंत्र मामलों में से प्रत्येक की जांच करें:

- (i) धारा 12एबी के तहत पंजीकृत राज चैरिटेबल ट्रस्ट को पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 5 लाख का कोष दान प्राप्त हुआ। ट्रस्ट पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान इसका उपयोग करने का इरादा रखता है और दावा किया है कि चूंकि दाता ने एक विशिष्ट दिशा के साथ दान दिया है कि यह ट्रस्ट के कॉर्पस की ओर है, यह धारा 11(1)(डी) के तहत कर से मुक्त है। . इसके अलावा, वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से ₹ 20 लाख का ऋण लिया और उसमें से ₹ 18 लाख अपने भवन के निर्माण पर लगाया। ट्रस्ट ने वर्ष के दौरान धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में ₹ 18 लाख का दावा किया।
- (ii) स्माइल फाउंडेशन एक 'लाभ के लिए नहीं' ट्रस्ट है जो एक माध्यमिक विद्यालय चलाता है। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान स्वैच्छिक योगदान और ट्रस्ट के सरकारी अनुदानों की कुल प्राप्तियां ₹30 लाख (क्रमशः ₹14 लाख और 16 लाख) थीं। क्या ट्रस्ट को धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है?
- (iii) मणि फाउंडेशन धारा 12एबी के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। 31.07.2021 को इसे अनुच्छेद 10(23सी) के तहत भी मंजूरी मिल जाती है। ट्रस्ट यह जानने का इरादा रखता है कि क्या वह धारा 11 और धारा 10 (23 सी) दोनों वर्गों के लाभों का आनंद ले सकता है।
- (iv) लिटिल एंजल्स धारा 12एए के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ संस्था है। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 11 और 12 में निहित छूट प्रावधानों के लाभों का दावा जारी रखने के लिए, यह धारा 12एबी के तहत पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है। धारा 12एबी के तहत पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रभावी तिथि क्या होगी?

ट्रस्ट यह पुष्टि करना चाहता है कि क्या धारा 12एबी के तहत दिए गए पंजीकरण की वही वैधता है जो धारा 12ए के तहत दी गई है। (8 अंक)

- (b) 51 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक श्री चेतन ने 1 अप्रैल 2018 को देश वाई में बसने के लिए भारत छोड़ दिया। लेकिन कुछ व्यक्तिगत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वह 1 जून 2021 को स्थायी रूप से भारत वापस आ गए।

उनके पास देश वाई में एक आवासीय संपत्ति है जिससे उन्होंने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए \$ 25,000 की आय अर्जित की। वह \$ 8,000 की मूल छूट सीमा के लिए पात्र है और शेष आय पर, उसने देश वाई में 20% की दर से आयकर का भुगतान किया। कर का भुगतान किया गया था 10 मई 2022 को भारत में उनके बैंक खाते से।

31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में व्यापार से उनकी आय ₹5,00,000 है। उन्होंने वर्ष के दौरान एक भारतीय कंपनी से ₹ 1,25,000 का लाभांश और एसबीआई के साथ बचत बैंक खाते पर ₹ 11,500 का ब्याज भी प्राप्त किया।

विभिन्न तिथियों पर 1 डॉलर की विनिमय दरें नीचे दी गई हैं:

1.04.2021 - ₹ 74; 31.03.2022, ₹ 75; 10.05.2022 - ₹ 75.5;

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में श्री चेतन की शुद्ध कर देयता की गणना इस धारणा पर करें कि भारत और देश वाई के बीच कोई डीटीए नहीं है।

मान लें कि निर्धारिती धारा 115बीएसी के प्रावधानों का विकल्प नहीं चुनता है।
(6 अंक)

उत्तर

- (a) (i) ₹ 5 लाख का सामूहिक दान कर से तभी मुक्त होगा जब उन्हें एक विशिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त किया जाता है कि वे कोष का हिस्सा बनेंगे और धारा 11(5) के तहत निर्दिष्ट किसी भी तरीके में निवेश किए जाएंगे।

यदि इस तरह से निवेश नहीं किया जाता है, तो यह पिछले वर्ष 2021-22 के लिए धारा 11(1)(डी) के तहत छूट प्राप्त नहीं होगी।

किसी ऋण या उधार से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय के आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए गए ₹ 20 लाख के ऋण में से ट्रस्ट द्वारा आवेदन किए गए ₹ 18 लाख को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, प्रासंगिक पिछले वर्ष में चुकौती की सीमा तक ऋण की चुकौती के समय आवेदन के रूप में दावा किया जा सकता है।

इसलिए राज चैरिटेबल ट्रस्ट के दोनों दावे सही नहीं हैं।

- (ii) स्माइल फाउंडेशन एक शिक्षा संस्थान है जो पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए।

यह सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, चूंकि ₹16 लाख का सरकारी अनुदान इसकी कुल प्राप्तियों का 53.33% है जो कि ₹30 लाख (₹14 लाख स्वैच्छिक योगदान + ₹16 लाख सरकारी अनुदान) है, जो कि इसकी कुल प्राप्तियों का 50% से अधिक है। .

संस्था की आय धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत छूट प्राप्त है।

इसलिए, धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) नहीं, ट्रस्ट धारा 11 और 10(23सी) दोनों के तहत लाभ नहीं उठा सकता है।

धारा 11 के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए धारा 12एबी के तहत मणि फाउंडेशन को दिया गया पंजीकरण 31.7.2021 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिस तारीख को इसे धारा 10(23सी) के तहत मंजूरी दी गई है।

ट्रस्ट, जिसका पंजीकरण निष्क्रिय हो गया है, धारा 12एबी के तहत अपने पंजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा करने पर, धारा 10(23सी) के तहत ऐसे ट्रस्ट को दिया गया अनुमोदन उस तारीख से प्रभावी नहीं होगा जिस दिन उक्त पंजीकरण क्रियाशील हो जाता है।

- (iv) धारा 12एबी के तहत पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रभावी तिथि 30.6.2021 है, जो 1 अप्रैल, 2021 से तीन महीने है। सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 16/2021 दिनांक 29.8.2021 के माध्यम से दिनांक को 31.3.2022 तक बढ़ा दिया है।

नहीं, धारा 12एबी के तहत प्रदान किया गया पंजीकरण केवल 5 वर्षों के लिए वैध होगा और हमेशा के लिए नहीं, जैसा कि धारा 12ए के तहत दिए गए पंजीकरण के मामले में होता है।

- (b) श्री चेतन भारत में रहने के बाद से निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवासी हैं पिछले वर्ष 2021-22 304 दिनों के लिए है जो उस पिछले वर्ष में 182 दिनों के न्यूनतम आवश्यक प्रवास से अधिक है। इसके अलावा, भारत में उनका प्रवास पिछले सात वर्षों के दौरान 1461 दिनों के लिए है (अर्थात्, पिछले वर्ष 2014-15 से पिछले वर्ष 2017-18 में प्रत्येक में 365 दिन + लीप वर्ष के लिए 1 दिन) (जो तत्काल पूर्ववर्ती 730 दिनों की न्यूनतम निर्दिष्ट आवश्यकता से अधिक है)। सात वर्ष) और वह पिछले वर्ष 2021-22 से ठीक पहले के 10 वर्षों में से 7 वर्षों (पिछले वर्ष 2011-12 से पिछले वर्ष 2017-18) में निवासी रहे हैं।

इसलिए, वह निवासी है और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है। तदनुसार, उनकी वैश्विक आय कर के अधीन होगी। हालांकि, वह देश वाई में अर्जित दोगुनी कर वाली आय के संबंध में धारा 91 के तहत कटौती के हकदार होंगे।

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री चेतन की कुल आय की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹	₹
गृह संपत्ति से आय [वाई देश में आवासीय संपत्ति] वार्षिक मूल्य ² (\$ 25,000 एक्स ₹ 75, 31.3.2022 को विनिमय दर)	18,75,000	
घटाएँ: एनएवी की धारा 24 - 30% के तहत कटौती	5,62,500	
		13,12,500
व्यवसाय या पेशे से होने लाभ और मुनाफे भारत में व्यापार से आय		5,00,000
अन्य स्रोतों से आय भारतीय कंपनी से लाभांश [₹1,25,000 x 100/90] एसबीआई के साथ बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,38,889 11,500	
		1,50,389
सम्पूर्ण कुल आय घटाएँ: अध्याय VIA के तहत कटौती धारा 80टीटीए के तहत - बचत बैंक खाते पर ब्याज (वास्तविक ब्याज ₹ 11,500 या ₹ 10,000, जो भी कम हो)		19,62,889 10,000
कुल आय		19,52,889
कुल आय (पूर्णांक में)		19,52,890

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री चेतन की कर देयता की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹
कुल आय पर कर [₹ 9,52,890 का 30% + ₹ 1,12,500]	3,98,367
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%	15,935
	4,14,302
घटाएँ: धारा 91 के तहत कटौती (नीचे वर्किंग नोट देखें)	1,78,500

²उचित किराया, नगरपालिका मूल्य आदि से संबंधित अन्य जानकारी के अभाव में किराये की आय को जीएवी के रूप में लिया गया है।

शुद्ध कर देयता	2,35,802
शुद्ध कर देयता (पूर्णांक)	2,35,800

कार्यात्मक टिप्पणियाँ: धारा 91 के तहत कटौती की गणना

विवरण (ब्यौरा)	₹	₹
भारत में कर की औसत दर [अर्थात्, [₹ 4,14,302/₹19,52, 890x100.]	21.21%	
एक्स देश में कर की औसत दर [20% of \$ 17,000 (\$ 25,000 - \$ 8,000) = \$ 3,400/\$ 25,000 x 100 = 13.6%	13.60%	
दोहरी कर आय		
मकान सम्पत्ति से आय	13,12,500	
₹ 13,12,500 @13.160% पर धारा 91 के तहत कटौती (औसत भारतीय कर दर (21.21%) और विदेशी कर दर (13.60%) से कम होना]		1,78,500

प्रश्न 4

- (a) निम्नलिखित स्वतंत्र मामले परिदृश्यों के संबंध में आपको 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर कटौती/स्रोत पर एकत्र किए गए कर और कर कटौती योग्य राशि से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
- (i) श्री रजत उम्र 79 वर्ष, एक सेवानिवृत्त निवासी व्यक्ति, एबीसी बैंक, दिल्ली के साथ एक बचत बैंक खाता (एस) और सावधि जमा खाता (एफ) रखता है। वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में एबीसी बैंक को निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:

(एस) पर ब्याज	₹ 75,100	
नियोक्ता से पेंशन (बचत खाते S में प्राप्त)	₹55,000	प्रति माह
सावधि जमा खाते से ब्याज (एफ)	₹1,20,000	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उनकी कोई अन्य आय नहीं है। मान लें कि श्री रजत ने धारा 115बीसीए का विकल्प नहीं चुना।

(ii) हाई एंड टॉल लिमिटेड, एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, ने श्री जॉन, एक निवासी व्यक्ति के साथ एक संयुक्त विकास समझौता किया, जिसके तहत श्री जॉन ₹ 6 करोड़ के आंशिक प्रतिफल के लिए 10 एकड़ भूमि का एक भूखंड हस्तांतरित करेंगे, जिसका भुगतान किया जाएगा। समझौते की तारीख, यानी 1.6.2021। हाई एंड टॉल लिमिटेड ने 31.3.2024 तक ऐसी जमीन पर गगनचुंबी अपार्टमेंट परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। परियोजना के पूरा होने पर, हाई एंड टॉल लिमिटेड अंतिम निपटान के रूप में श्री जॉन को अपार्टमेंट में 6 फ्लैटों को स्थानांतरित करेगा। 31.3.2024 को प्रत्येक फ्लैट का एफएमवी ₹ 1.20 करोड़ होने का अनुमान है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 12 करोड़ के कुल कारोबार वाली एक घरेलू कंपनी मैसर्स आर्यन लिमिटेड ने पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान मैसर्स वरुण एंड कंपनी से ₹ 85 लाख (खरीद वापसी को छोड़कर) का सामान खरीदा। मैसर्स वरुण एंड कंपनी, एक निवासी फर्म, ने अपना पैन आर्यन लिमिटेड को प्रस्तुत किया है, मैसर्स वरुण (पी) लिमिटेड से खरीद के लिए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

25.05.2021 को - ₹30 लाख; 28.06.2021 को - ₹25 लाख; 10.12.2021 को - ₹ 20 लाख (इन खरीदों में से ₹ 5 लाख का सामान गुणवत्ता के मुद्दे के कारण 20.12.2021 को वापस कर दिया गया था जिसके लिए मैसर्स वरुण एंड कंपनी द्वारा पैसा वापस कर दिया गया था); 20.02.2022 को - ₹10 लाख। मान लें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मैसर्स वरुण एंड कंपनी का कारोबार ₹ 8 करोड़ था और उपरोक्त राशि को जमा किया गया था मैसर्स आर्यन लिमिटेड की पुस्तकों में मैसर्स वरुण एंड कंपनी का खाता उसी तारीख को।

(iv) तेलंगाना राज्य सरकार ने 1.09.2021 को मैसर्स एक्सवाइजेड कंपनी लिमिटेड को कोयला खदान का पट्टा प्रदान किया और पट्टे के लिए 10 करोड़ रुपये कर किए। मैसर्स एक्सवाइजेड कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान

मैसर्स एबी (पी) लिमिटेड को ₹ 1 करोड़ का कोयला बेचा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मैसर्स एक्सवार्डजेड कंपनी और मैसर्स एबी (पी) लिमिटेड का कारोबार क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 6 करोड़ रुपये था। (8 अंक)

- (b) अल्फा लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया, बीटा लिमिटेड, भारत में 30% इक्विटी शेयर रखती है। बीटा लिमिटेड सॉफ्टवेयर विकसित करता है और संबंधित सहायता सेवाएं भी प्रदान करता है। बीटा लिमिटेड ने वर्ष के दौरान अल्फा लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया को ₹ 2,500 प्रति व्यक्ति घंटे की दर से 150 मानव-घंटे के लिए बिल भेजा। इस कार्य को करने की कुल लागत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) ₹ 3,50,000 थी।

हालांकि, बीटा लिमिटेड ने गामा लिमिटेड, भारत को श्रमशक्ति के समान स्तर के लिए ₹ 3,500 प्रति मानव घंटे की दर से बिल किया और अपनी लागत पर 40% का सकल लाभ अर्जित किया।

अल्फा लिमिटेड और गामा लिमिटेड के साथ बीटा लिमिटेड के लेन-देन तुलनीय हैं, निम्नलिखित अंतरों के अधीन:

- (i) जबकि बीटा लिमिटेड भी अल्फा लिमिटेड से तकनीकी सहायता प्राप्त करता है, गामा लिमिटेड से ऐसा कोई समर्थन नहीं है। अल्फा लिमिटेड से प्राप्त तकनीकी सहायता का मूल्य सामान्य सकल लाभ का 15% रखा जा सकता है,
- (ii) जैसा कि अल्फा लिमिटेड बड़ी मात्रा में व्यापार देता है, बीटा लिमिटेड ने अल्फा लिमिटेड को पेशकश की, एक मात्रा छूट जो सामान्य सकल लाभ के 10% पर मूल्यवान हो सकती है,
- (iii) अल्फा लिमिटेड को सेवाएं प्रदान करने के मामले में, बीटा लिमिटेड न तो कोई जोखिम उठाता है और न ही कोई विपणन लागत वहन करता है। दूसरी ओर, गामा लिमिटेड को सेवाओं के मामले में, बीटा लिमिटेड को विपणन कार्य से जुड़े सभी जोखिमों और लागतों को वहन करना होगा जो सामान्य सकल लाभ का 20% अनुमानित हो सकता है,
- (iv) बीटा लिमिटेड ने अल्फा लिमिटेड को एक महीने के ऋण की पेशकश की इस तरह के ऋण प्रदान करने की लागत सामान्य सकल लाभ के 5% पर आंका जा सकता है। गामा लिमिटेड को ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया

लागत से अधिक विधि के तहत समायोजित की जाने वाली आय के साथ-साथ सन्निकट मूल्य की गणना करें। (6 अंक)

उत्तर

- (a) (i) श्री रजत धारा 194पी के अनुसार एक निर्दिष्ट व्यक्ति हैं क्योंकि उनकी आयु 79 वर्ष है, पेंशन आय और एबीसी बैंक के साथ सावधि जमा पर केवल ब्याज है। उनकी पेंशन आय एबीसी बैंक के साथ बचत बैंक में भी प्राप्त होती है।

धारा 194पी के अनुसार, एबीसी बैंक (निर्दिष्ट बैंक) को आयु के लिए श्री रजत की कुल आय पर लागू दरों के आधार पर स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। 2022-23, को प्रभावी करने के बाद गणना -

- अध्याय VI-A के तहत स्वीकार्य कटौती; तथा
- धारा 87A के तहत स्वीकार्य छूट

विवरण (ब्यौरा)	₹	₹
पेंशन (₹55,000 x 12)	6,60,000	
घटाएँ: धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती	50,000	6,10,000
सावधि जमा पर ब्याज	1,20,000	
बचत बैंक खाते पर ब्याज	75,100	1,95,100
सम्पूर्ण कुल आय		8,05,100
धारा 80टीटीबी के तहत कटौती [सावधि जमा और बचत खाते पर ब्याज, 50,000 तक सीमित है, क्योंकि श्री रजत 79 वर्ष की आयु के निवासी भारतीय हैं]		50,000
कुल आय		7,55,100
निर्दिष्ट बैंक यानी एबीसी बैंक द्वारा काटा जाने वाला कर [20% एक्स ₹ 2,55,100 (₹ 7,55,100 - ₹ 5,00,000) + ₹ 10,000 (₹ 2,00,000 का 5% होने के नाते)] मूल्य से अधिक एचईसी@4%		63,461

- (ii) श्री जॉन, एक निवासी, हाई एंड टॉल लिमिटेड, एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ एक समझौता कर रहा है, जिसमें अपार्टमेंट में 6 करोड़ और 6 फ्लैटों के विचार में अपनी भूमि पर एक उच्च वृद्धि वाले अपार्टमेंट परिसर का विकास किया जाएगा। यह धारा 45(5ए) के तहत एक निर्दिष्ट समझौता है।

धारा 194-आईसी के अनुसार, हाई एंड टॉल लिमिटेड को श्रीमान जॉन के साथ एक निर्दिष्ट समझौते के तहत, ₹ 6 करोड़ पर 10% स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है, जो कि वस्तु के रूप में प्रतिफल के अलावा भुगतान किया गया विचार है।

ऐसी राशि या भुगतान, जो भी पहले हो, के ऋण के समय कर काटा जाना है।

धारा 194-आईसी के तहत कर = ₹ 6 करोड़ एक्स 10% = ₹ 60 लाख होगा

- (iii) मैसर्स वरुण एंड कंपनी को माल की बिक्री पर स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है मैसर्स आर्यन लिमिटेड, चूंकि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए उनका कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक नहीं है।

Pवाई के लिए मैसर्स आर्यन लिमिटेड के कारोबार के बाद से 2020-21 ₹ 10 करोड़ से अधिक है और मैसर्स वरुण एंड कंपनी से खरीद का कुल मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक है, मैसर्स आर्यन लिमिटेड को ₹ 50 से अधिक की ऐसी राशि के धारा 194क्यू@0.1% के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है लाख। हालाँकि, धारा 194क्यू के प्रावधान 1.7.2021 से लागू हैं।

खरीद वापसी के मामले में, यदि विक्रेता द्वारा पैसा वापस कर दिया जाता है, तो खरीद वापसी पर काटे गए इस कर को उसी विक्रेता से अगली खरीद के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

मैसर्स वरुण एंड कंपनी से खरीद पर टीडीएस की प्रयोज्यता		
25.05.2021	₹30 लाख	स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है
28.06.2021	₹25 लाख	खरीद का सकल मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक है लेकिन फिर भी मैसर्स आर्यन लिमिटेड को धारा

		194क्यू के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 194क्यू के प्रावधान केवल 1.7.2021 से प्रभावी हैं
10.12.2021	₹20 लाख	TDS = ₹ 2,000 [0.1% x ₹ 20 lakhs]
20.02.2022	₹10 लाख	टीडीएस = ₹ 500 [₹ 1,000, 0.1% एक्स ₹ 10 लाख - ₹ 500, ₹ 5 लाख की खरीद वापसी पर टीडीएस होने के नाते]

- (iv) राज्य सरकार को कोयले की खान के पट्टे के लिए शुल्क होने के कारण ₹ 10 करोड़ पर धारा 206सी(1सी) के तहत 2% की दर से स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

$$\text{TCS} = 2\% \times ₹ 10 \text{ करोड़} = ₹ 20,00,000$$

मैसर्स एक्सवार्डजेड कंपनी लिमिटेड को मैसर्स एबी (पी) लिमिटेड को कोयले की बिक्री पर धारा 206सी(1) के तहत 1% की दर से स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

$$\text{TCS} = 1\% \text{ of } ₹ 1 \text{ करोड़} = ₹ 1,00,000.$$

- (b) दो उद्यमों को संबद्ध उद्यम माना जाता है जहां एक उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे उद्यम में 26% से कम मतदान शक्ति वाले शेयर रखता है।

इस मामले में, चूंकि अल्फा लिमिटेड, एक विदेशी कंपनी, बीटा लिमिटेड में 30% इक्विटी शेयर रखती है, एक भारतीय कंपनी, अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड को संबद्ध उद्यम माना जाता है। चूंकि बीटा लिमिटेड द्वारा अल्फा लिमिटेड को सॉफ्टवेयर विकसित करने और संबंधित सहायता सेवा प्रदान करने का लेनदेन संबद्ध उद्यमों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन है, इसलिए इस मामले में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान आकर्षित होंगे।

कॉस्ट प्लस मेथड के अनुसार आर्म की लेंथ प्राइस की गणना

विवरण (ब्यौरा)	%	%
गामा लिमिटेड लिमिटेड [एक असंबंधित पार्टी] के मामले में लागत पर सकल लाभ मूल्यवृद्धि		40%
घटाएँ: कार्यात्मक और अन्य अंतरों के लिए समायोजन		
- प्रौद्योगिकी समर्थन का मूल्य [अल्फा लिमिटेड प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करता है, लेकिन गामा लिमिटेड ऐसा समर्थन प्रदान नहीं करता है। इसलिए, प्रौद्योगिकी समर्थन का मूल्य समायोजित किया जाएगा] [40% का 15%, सकल लाभ होने के नाते]	6%	
- अल्फा लिमिटेड को मात्रा छूट [अल्फा लिमिटेड को मात्रा छूट की अनुमति है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में व्यापार देता है, लेकिन गामा लिमिटेड को यह प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए इसे समायोजित किया जाएगा] [40% का 10%, सकल लाभ होने के नाते]	4%	
- विपणन से जुड़ा जोखिम और लागत [बीटा लिमिटेड को गामा लिमिटेड के मामले में विपणन कार्य से जुड़े सभी जोखिम और लागत वहन करनी होगी, जबकि अल्फा लिमिटेड की सेवाओं के मामले में ऐसा कोई जोखिम नहीं है, इसलिए बाजार जोखिम और लागत को समायोजित किया जाएगा।] [40% का 20%, सकल लाभ होने के नाते]	8%	18%
		22%
जोड़: अल्फा लिमिटेड को ऋण की लागत [बीटा लिमिटेड ने अल्फा लिमिटेड को 1 महीने का ऋण प्रदान किया है लेकिन असंबद्ध पार्टी को नहीं। इसलिए, एएलपी पर पहुंचने के लिए इस तरह के क्रेडिट की लागत के लिए समायोजन किया जाना चाहिए] [(40% का 5%, सकल लाभ होने के नाते)]		2%

आर्म्स लेन्थ सकल लाभ मार्क अप टू कॉस्ट	<u>24%</u>
अल्फा लिमिटेड के काम को अंजाम देने के लिए बीटा लिमिटेड द्वारा खर्च की गई लागत	3,50,000
जोड़ें: समायोजित सकल लाभ (₹3,50,000 x 24%)	<u>84,000</u>
आर्म्स लेन्थ का बिल मान	4,34,000
घटाएँ: अल्फा लिमिटेड से वास्तविक बिल की गई आय (₹ 2,500 एक्स 150 मानव घंटे)	<u>3,75,000</u>
बीटा लिमिटेड की कुल आय में वृद्धि की जाएगी	<u>59,000</u>

प्रश्न 5

(a) आपके उत्तर में इन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

- मुद्दा शामिल है
- प्रावधान लागू
- विश्लेषण और
- निष्कर्ष

(i) श्री एक्स ने अपनी कुल आय ₹ 10 लाख की घोषणा करते हुए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय की विवरणी दाखिल की। उनके मामले को संवीक्षा मूल्यांकन के लिए चुना गया था और निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ खर्चों की अस्वीकृति के कारण ₹ 4 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। मूल्यांकन की कार्यवाही के दौरान, श्रीमान एक्स ने पाया कि वह गलती से धारा 72 के तहत ₹ 3 लाख की राशि के अग्रोषित नुकसान के संग्रह-ऑफ का दावा करने में विफल रहा, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार था। श्री एक्स द्वारा त्रुटि का पता चलने तक, संशोधित रिटर्न भरने की समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी थी। इसलिए, कार्यवाही के दौरान, श्री एक्स ने आकलन अधिकारी से आगे लाए गए घाटे के संग्रह की अनुमति देने के लिए संपर्क किया, जो गलत तरीके से धारा 139(1) के तहत दायर आय की वापसी में दावा नहीं किया गया था। क्या निर्धारण अधिकारी श्रीमान एक्स के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य है?

या

दिनांक 14.10.2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत एक निवासी व्यक्ति श्री साहिर के परिसरों की तलाशी ली गई। निर्धारिती के बैंक खाते के सत्यापन पर, ₹ 20 करोड़ की राशि निर्धारिती के बैंक खाते में जमा की गई पाई गई। निर्धारण अधिकारी ने ऐसी राशि को धारा 68 के तहत अस्पष्ट नकद ऋण के रूप में जोड़ा। अपील पर, निर्धारिती ने घोषणा की कि राशि उसके करीबी दोस्तों में से एक श्री शेखर से प्राप्त हुई थी। श्री शेखर निर्धारिती के खाते में ऐसी राशि हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुए। हालांकि, निर्धारण अधिकारी का मानना है कि चूंकि श्री शेखर इस राशि के स्रोत की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, इसलिए इसे निर्धारिती के हाथ में अस्पष्ट नकद ऋण के रूप में माना जाना चाहिए।

क्या निर्धारण अधिकारी का दावा उचित है?

- (ii) मई, 2020 को, एक निवासी व्यक्ति, डी वेंकटस्वामी ने एबीसी प्राइवेट से 1,000 बोनस शेयर प्राप्त किए। लिमिटेड जिसमें उनके पास 1,000 इक्विटी शेयर थे। निर्धारण अधिकारी ने कहा कि चूंकि निर्धारिती ने बोनस शेयरों के लिए कोई प्रतिफल नहीं दिया है, इसलिए वह अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(c) के तहत अन्य स्रोतों से आय के रूप में बाजार मूल्य की पेशकश करने के लिए कानून में बाध्य था। निर्धारण अधिकारी ने इन बोनस शेयरों के उचित मूल्य की गणना की और राशि को डी वेंकटस्वामी की आय में "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में जोड़ा।

क्या निर्धारण अधिकारी का निर्णय विधि की दृष्टि से सही है ? (4 x 2 = 8 अंक)

- (b) सन लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी, कालीनों के निर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। अपनी अंतरराष्ट्रीय बिक्री का विस्तार करने के लिए, उसने ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए लंदन स्थित कंपनी शाइन इंक की सेवाएं लीं। शाइन इंक का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान, सन लिमिटेड ने ऐसी सेवाओं के लिए शाइन इंक को 5 लाख रुपये का भुगतान किया

और 15.03.2022 को इक्वलाइजेशन लेवी घटा दी और इसे 15.04.2022 को केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया।

आप की आवश्यकता है -

- (i) इक्वलाइजेशन लेवी के विलंबित भुगतान पर सन लिमिटेड पर लगने वाले ब्याज की गणना करें।
- (ii) किन परिस्थितियों में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है?
- (iii) सन लिमिटेड जुर्माना लगाने के आदेश से व्यथित है। जुर्माना लगाने वाले निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?

(6 अंक)

उत्तर

(a)(i) [पहला विकल्प]

मुद्दा शामिल है: विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या निर्धारण अधिकारी धारा 72 के तहत अग्रेषित नुकसान के संग्रह-ऑफ की अनुमति देने के लिए बाध्य है, भले ही निर्धारिती, श्री एक्स, ने इस मामले में उनके द्वारा दाखिल रिटर्न और समय में इसका दावा नहीं किया हो। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सीमा समाप्त हो गई है।

प्रावधान लागू: धारा 72 के तहत, व्यावसायिक घाटे को आगे बढ़ाया जाएगा और अगले निर्धारण वर्ष में किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यह माना जाता है कि निर्धारिती ने धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय के भीतर आय की विवरणी दाखिल की है और इसलिए बाद के वर्ष में अनवशेषित हानि के समायोजन के लिए पात्र है।

धारा 72 में इस्तेमाल किया गया शब्द "करेगा", यह दर्शाता है कि अग्रेषित व्यापार हानि के समायोजन से संबंधित प्रावधान अनिवार्य हैं, बशर्ते नुकसान किसी भी पिछले वर्ष में धारा 139(3) के तहत दाखिल रिटर्न के अनुसरण में निर्धारित किया गया हो।

विश्लेषण: 1955 दिनांक 11.04.1955 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 14 (एक्सएल -35) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह

करदाता की हर उचित तरीके से सहायता करे, विशेष रूप से राहत का दावा करने और हासिल करने के मामले में, और इस संबंध में, वे करदाता का मार्गदर्शन करने में पहल करनी चाहिए, जहां कार्यवाही या उनके सामने अन्य विवरण इंगित करते हैं कि उसका कुछ प्रतिदाय या राहत देय है।

इस प्रकार, यह निर्धारण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह श्रीमान एक्स की कुल आय और परिणामी कर देयता के सही आंकड़े का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करे। केवल इसलिए कि श्रीमान एक्स ने फ़ाइल की गई मूल रिटर्न में ₹ 3 लाख की अग्रेनीत हानियों के समायोजन का दावा नहीं किया है और संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा समाप्त हो गई है, यह कर निर्धारण अधिकारी को धारा 72 को लागू करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता है। उपयुक्त मामला।

निष्कर्ष: निर्धारण अधिकारी श्रीमान एक्स के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और धारा 72 के तहत ₹ 3 लाख के अग्रेषित नुकसान के संग्रह-ऑफ की अनुमति देता है, भले ही श्री एक्स ने दायर रिटर्न में इसका दावा नहीं किया हो, और दाखिल करने की समय सीमा संशोधित रिटर्न समाप्त हो गया है।

नोट - प्रश्न में दिए गए तथ्य सीआईटी बनाम महालक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (1986) 160 आईटीआर 920 के तथ्यों के समान हैं, जिसमें उपरोक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। उपरोक्त उत्तर उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के औचित्य पर आधारित है, जिसमें 11.04.1955 के 1955 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 14 (एक्सL-35) को ध्यान में रखा गया है।

[दूसरा विकल्प]

मुद्दा शामिल है: इस मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या नकद ऋण वास्तविक होने के लिए निर्धारिती को ऋणदाता के पास राशि के स्रोत की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

प्रावधान लागू: धारा 68 एक निर्धारिती की पुस्तकों में जमा पाई गई किसी भी राशि पर कर लगाती है, जहां निर्धारिती प्रकृति और उसके स्रोत के बारे में

स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

विश्लेषण: कैश ऋण के वास्तविक होने के लिए, श्री साहिर को लेनदार, श्री शेखर की पहचान, इस मामले में, लेनदार की अग्रिम धन देने की क्षमता और अंत में, लेन-देन की वास्तविकता को साबित करना होगा।

श्री शेखर से केवल पुष्टि पर्याप्त नहीं होगी।

निष्कर्ष: तदनुसार, श्री साहिर के हाथों अस्पष्टीकृत नकद ऋण को कर में लाने की निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई सही है, क्योंकि उनके मित्र श्री शेखर, जिनसे उन्होंने ₹ 20 करोड़ प्राप्त किए थे, जो उनके (श्री साहिर के) बैंक खाते में जमा पाए गए थे। , अपने हाथ में इस राशि के स्रोत की व्याख्या करने में असमर्थ हैं।

नोट - प्रश्न में दिए गए तथ्य सीआईटी बनाम सादिक शेख (2020) 429 आईटीआर 163 के तथ्यों के समान हैं, जिसमें उपरोक्त मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आया था। उपरोक्त उत्तर उस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के तर्क पर आधारित है।

- (ii) **मुद्दा शामिल है:** विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या शेयरधारकों द्वारा प्राप्त बोनस शेयर धारा 56(2)(एक्स) के प्रावधानों के अनुसार 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत कर योग्य होंगे, क्योंकि वे बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त हुए हैं।

प्रावधान लागू: धारा 56(2)(एक्स) किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल के या किसी व्यक्ति से अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त किसी भी राशि या संपत्ति के मूल्य पर कर लगाती है।

विश्लेषण: जब एक शेयरधारक को बोनस शेयर मिलते हैं, तो उसके द्वारा रखे गए मूल शेयरों का मूल्य नीचे चला जाता है और बाजार मूल्य के साथ-साथ दो शेयरों का आंतरिक मूल्य समान या लगभग समान होगा जैसा बोनस शेयर जारी करने से पहले मूल शेयर के मूल्य के लगभग समान होगा।

इस प्रकार, बोनस शेयरों की प्राप्ति के कारण करदाता शेयरधारक द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ को मूल रूप से उसके द्वारा रखे गए न्यायसम्य शेयरों के मूल्य में मूल्यहास द्वारा समायोजित किया जाता है

निष्कर्ष: तदनुसार, डी वेंकटस्वामी के अन्य स्रोतों से आय के रूप में बोनस शेयरों के उचित मूल्य को शामिल करने में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई गलत है।

नोट - प्रश्न में दिए गए तथ्य पीसीआईटी बनाम डॉ रंजन पई (2021) 431 आईटीआर 250 के तथ्यों के समान हैं, जिसमें मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष आया था। उपरोक्त उत्तर उक्त मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के तर्क पर आधारित है।

(b) (i) समकरण लेवी के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज

इक्वलाइजेशन लेवी = ₹ 5 लाख का 6% = ₹ 30,000

15.3.2022 को काटे गए इक्वलाइजेशन लेवी का भुगतान 7.4.2022 (अर्थात् अगले महीने की 7 तारीख) तक केंद्र सरकार के ऋण में किया जाना है।

हालाँकि, इस मामले में, सन लिमिटेड ने केवल 15.4.2022 को ही भुगतान किया।

इस मामले में 8 दिन की देरी है।

साधारण ब्याज @ 1% प्रति माह या महीने के हिस्से के लिए लगाया जाता है जिससे कर जमा करने में देरी होती है।

तदनुसार, ब्याज ₹ 30,000 का 1% होगा = ₹ 300

(ii) किन परिस्थितियों में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है

यदि सन लिमिटेड मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित करता है कि उक्त विफलता के लिए उचित कारण था, तो कटौती या समतुल्यकरण लेवी का भुगतान करने में विफलता के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सन लिमिटेड को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(ii) अपील दायर करने की समय सीमा

यदि सन लिमिटेड जुर्माना लगाने के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह जुर्माना लगाने वाले निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त (अपील) से अपील कर सकता है।

प्रश्न 6

(a) कारण सहित बताएं कि क्या निम्नलिखित कृत्यों को कर नियोजन या कर प्रबंधन या कर अपवंचन माना जा सकता है।

(i) एक व्यक्ति निर्धारित अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में ₹ 10,000 की राशि जमा करता है, जिससे उसकी कुल आय ₹ 5,05,000 से घटकर ₹ 4,95,000 हो जाती है जो उसे धारा 87ए के तहत छूट का हकदार बनाता है और फलस्वरूप उसकी कर देनदारी शून्य हो जाती है।

(ii) एक कंपनी जो ग्राहकों से फॉर्म संख्या 60 में घोषणा प्राप्त करती है, जिन्हें अपना पैन प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन उन्हें आवंटित नहीं किया गया है।

(iii) एक साझेदारी फर्म ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए ₹ 35,000 का भुगतान किया जो एक भागीदार के आवास पर स्थापित है। हालाँकि, इसे मूल्यहास का दावा करने के लिए फर्म के कार्यालय में स्थापित किया गया दिखाया गया है।

(iv) एक कंपनी श्रीमती डी (निदेशक श्री डी की पत्नी) को 4 लाख रुपये का भुगतान करती है, जो एक योग्य पेशेवर होने के बावजूद एक गृहिणी हैं। इसका उद्देश्य श्रीमती डी की कुल आय (₹ 5 लाख तक) को बढ़ाना और कंपनी को श्रीमती डी द्वारा किसी भी पेशेवर सेवा के प्रावधान के बिना कंपनी की पुस्तकों में दावा व्यय करना है।

(4 अंक)

(b) डी लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही के संबंध में, श्री प्रतीक को "आधिकारिक समनुदेशिती" के रूप में नियुक्त किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में।

(4 अंक)

- (c) डिजिटल अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ई-कॉमर्स में कराधान के मुद्दे क्या हैं? कार्य योजना 1 के तहत ओईसीडी की सिफारिशों को सूचीबद्ध करें जो डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। (6 अंक)

उत्तर

(a)

	उत्तर:	कारण
(i)	कर योजना	धारा 80सी के तहत कटौती का दावा करने के लिए अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा जमा करना, धारा 87ए के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए कुल आय को 5,05,000 से घटाकर 4,95,000 करना, जिससे उसकी कर देनदारी 'शून्य' हो जाती है, आयकर कानून के प्रावधानों के तहत अनुमत कर नियोजन उपाय।
(ii)	कर प्रबंधन	कंपनी द्वारा फॉर्म संख्या 60 में ग्राहकों से घोषणा प्राप्त करना आयकर कानून के तहत वैधानिक दायित्व के अनुपालन की प्रकृति में है।
(iii)	कर की चोरी	एक भागीदार के निवास पर एक रेफ्रिजरेटर लगाया गया है और मूल्यहास का दावा करने के लिए फर्म के कार्यालय में स्थापित के रूप में दिखाया गया है, यह कर से बचने के प्रयास के साथ गलत विवरण प्रस्तुत करने के समान होगा।
(iv)	कर की चोरी	श्रीमती डी (निदेशक श्री डी की पत्नी) को किसी भी पेशेवर सेवाओं के प्रावधान के बिना ₹ 4 लाख का भुगतान, उनकी कुल आय को ₹ 5 लाख तक बढ़ाने के लिए और तदनुसार कंपनी की कुल आय को कम करने के लिए कंपनी की कर देयता को कम करने का एक तरीका है। कंपनी एक काल्पनिक लेनदेन आंकड़ों करके। कंपनी 30%/25%/22% की समान दर पर कर के लिए उत्तरदायी है, जैसा भी मामला हो, जबकि श्री रमण किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे,

		चूँकि, उसकी कुल आय ₹5,00,000 से अधिक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वह धारा 87ए के तहत ₹12,500 की कर छूट के लिए पात्र होगा। एक काल्पनिक लेनदेन को रिकॉर्ड करके कर देयता को कम करना कर चोरी के समान होगा।
--	--	---

- (b) सीबीडीटी परिपत्र नंबर 4/2019, दिनांक 28.1.2019 ने स्पष्ट किया है कि चूँकि आधिकारिक समनुदेशिती आय प्राप्त नहीं करता है या देनदार की ओर से संपत्ति का प्रबंधन नहीं करता है, इसलिए उसे अधिनियम के तहत देनदार का 'प्रतिनिधि निर्धारिती' नहीं माना जा सकता है। देनदार की संपत्ति से उत्पन्न होने वाली कर-देयता की गणना करना। इसलिए, डी लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही के संबंध में "आधिकारिक समनुदेशिती" के रूप में नियुक्त श्री प्रतीक को प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में नहीं माना जाएगा।

चूँकि दिवालिया की संपत्ति आधिकारिक असाइनी के पास अधिनियम/कानून के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार आधिकारिक असाइनी के कामकाज को विनियमित करने के लिए निहित है, इसलिए उन्हें आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक 'न्यायिक इकाई' के रूप में माना जाना चाहिए।

अधिनियम के तहत कर-देयता के निर्वहन के उद्देश्य से, आधिकारिक समनुदेशिती की स्थिति धारा 2(31)(vii) में निर्धारित 'कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति' की है, जो धारा 2 (31) (i) से (vi) में आने वाले 'व्यक्तियों' में से एक नहीं है।

इसलिए, आधिकारिक समनुदेशिती को इस मामले में दिवालिया, डी लिमिटेड की प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से 'कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति' के लिए लागू आईटीआर फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है, और आय के अनुसार कर लगाया जाएगा किसी विशेष वर्ष में 'कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति' के लिए लागू दरें।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आधिकारिक समनुदेशितियों को दिवालिया की प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अलग पैन प्राप्त करना होगा।

- (C) डिजिटल अर्थव्यवस्था में लेन-देन जैसे बिक्री, खरीद, भुगतान, सेवाएं प्रदान करना डिजिटल या वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल डोमेन में,

व्यवसाय वास्तव में किसी भौतिक स्थान पर नहीं होता है बल्कि "साइबरस्पेस" में होता है।

ई-कॉमर्स में कराधान के मुद्दे

ई-कॉमर्स से संबंधित विशिष्ट कराधान मुद्दे हैं:

- (i) भुगतान की प्रकृति को चिह्नित करने और कर योग्य लेनदेन, गतिविधि और कर क्षेत्राधिकार के बीच एक संबंध या लिंक स्थापित करने में कठिनाई,
- (ii) लेन-देन, गतिविधि का पता लगाने और आयकर उद्देश्यों के लिए करदाता की पहचान करने में कठिनाई।

डिजिटल अर्थव्यवस्था से निपटने वाली कार्य योजना 1 के तहत ओईसीडी की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- (1) यह प्रदान करने के लिए मौजूदा स्थायी स्थापना (पीई) नियम को संशोधित करना क्या पूरी तरह से डी-मटेरियलाइज्ड डिजिटल गतिविधियों में लगा कोई उद्यम पीई का गठन करेगा, अगर उसने किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण डिजिटल उपस्थिति बनाए रखी है।
- (2) पीई की अवधारणा में व्यापार पीई का एक आभासी निश्चित स्थान यानी, एक पीई का निर्माण जब उद्यम एक अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी अन्य उद्यम के सर्वर पर एक वेबसाइट रखता है और उस वेबसाइट के माध्यम से व्यवसाय करता है।
- (3) किसी विदेशी ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं के लिए कुछ भुगतानों पर अंतिम रोक टैक्स लगाना या किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी से या किसी अन्य अनुबंधित राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी से प्राप्त कुछ डिजिटल लेनदेन के लिए प्रतिफल पर एक समीकरण उदग्रहण का अधिरोपण।